

पत्रांक ३९५८ / आयु०क०उत्तरा० / विधि—अनुभाग / ०९—१० / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि—अनुभाग)
दिनांक: देहरादून: / ६ दिसम्बर—०९

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क०नि०)वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर ।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी ।

मुख्यालय के पत्र संख्या—३८९९ / आयु०क०उत्तरा० / विधि—अनुभाग / ०९—१० / देहरादून दिनांक १०—१२—२००९ के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में होटलों पर सुख साधन कर नियमावली २००९ से सम्बन्धित अधिसूचना की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। इसी क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या—३९२३ / आयु०क०उत्तरा० / विधि—अनुभाग / ०९—१० / देहरादून दिनांक १४—१२—२००९ के माध्यम से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू राजस्व वित्त अधिनियम—१९७५ की प्रतियां हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की गयी थी। उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू राजस्व विधि अधिनियम—१९७५) अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश २००२ के रूप में लागू है। संदर्भित अधिसूचना दिनांक ०९—११—२००२ की प्रतिलिपि, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू राजस्व विधि (संशोधन अधिनियम—१९९४) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६ / १९९४) की प्रतिलिपि, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू राजस्व विधि (संशोधन अधिनियम—१९९९) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४ / १९९९) की प्रतिलिपि भी इसी क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संगलन—उपरोक्तानुसार ।

(वी०क०स्क्सेना)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), कर
उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं० ३९५८ / दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रमुख सचिव, वित उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
२. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रानगर, देहरादून।
३. अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।
४. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून / कुमार्यू जोन, रुद्रपुर।
५. एडीशनल कमिश्नर(आडिट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।

6. समस्त ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीन्स्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. ज्वाइंट कमिशनर(अपील)वाणिज्य कर, देहरादून/ हल्द्वानी।
8. ज्वाइंट कमिशनर(विभागीय/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनोआईसी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10. श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 225 आर्शीवाद इल्कलैव देहरादून।
11. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य० परियोजना कार्यालय आई०आई०टी०रुड़की।
12. संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13. इन्टावैट ईन्फो प्रा०लि०४, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर०सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।
14. नेशनल लॉ हाउस बी—२ मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
15. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—१५/५ राजनगर गाजियाबाद।
16. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्र कम्पाउण्ड राजनगर, गाजियाबाद।
17. डिप्टी कमिशनर(उच्च न्याय०कार्य०)वाणिज्य कर, नैनीताल।
18. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19. दी होलसेल डीलर्स एसो० १४, आढ़त बाजार देहरादून।
20. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो० २२२/५ गॉधी ग्राम, देहरादून।
21. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
22. विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

एडीशनल कमिशनर(प्रशासन), कर
उत्तराखण्ड।

उत्तरांचल शासन

पर्यटन अनुभाग।

संख्या:- १५८८८/२००२-३४६८/२००२
देहरादून, उत्तरांचल दिनांक ७/१/२००२

आधिकारिक सूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा नियन्त्रण के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन या उपांत्तर कर सकती है, जो आवश्यक व सर्वार्थीन हैं।

चूंकि "उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्व विधि अधिनियम, 1975 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(आधिनियम संख्या २४ सन् २०००) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि "उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्व विधि अधिनियम, 1975" उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगा:-

उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्व विधि अधिनियम, 1975)
अनुकूलन एवं उपांत्तरण आदेश, 2002.

1—संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (1) यह आदेश उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांत्तरण आदेश, 2002 कहलायगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।
- (3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2—"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना:-

उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्व विधि—अधिनियम 1975 में जहाँ—जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश" आमा है वहाँ वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

[Signature]
(एन०एन० प्रसाद)
सचिव।

पु0प0सं0— 559 / (1) / 2002, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
- 2— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- 3— समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कुमाऊँ मण्डल।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल सरकार, देहरादून।
- 7— निबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 8— उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को दिनोंक ७/८/०२ के विधायी परिशिष्ट, भाग-४, खण्ड-ख के असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25-25 प्रतियां शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आदर्श प्रेषित। उत्तरांचल के सभी सचिव, सचिव, सचिव, सचिव,

आज्ञा सं.

(एन०एन० प्रसाद)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रशिक्षित अनुभाग

संख्या-2086/41-94-496/89

लिखान: पिनांक: 12 अक्टूबर, 1994

उथम

सेवोधान

गोप्यता

=====

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि संशोधन आधीनयन,
1994। उत्तर प्रदेश आधीनियम संख्या 26 सन् 1994 की धारा-1 की
उपधारा ॥२॥ के अधीन शोक्त का प्रयोग करके राज्यपाल 12 अक्टूबर, 1994
को ऐसा दिनांक निरापत्ति करते हैं जब उक्त आधीनियम प्रयुक्त होगा।

आज्ञा है,

शाशांकशेखर तंह

प्रमुख सचिव ।

संख्या: 2086/41-94-496/89, तदीदनांक

प्रतीलीप निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

॥१॥ सौचव, विधान रागा, उत्तर प्रदेश ।

॥२॥ सौचव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।

॥३॥ सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

॥४॥ निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश ।

॥५॥ निदेशक, राज्यीय मुद्रणालय, सेशबाग, नखनऊ को इस आकाश के राध
प्रैक द्वारा इसे बाणी के आगामी अंक में पुकारीशत करने का कष्ट करें ।

॥६॥ संसदीय कार्य अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5

आज्ञा है,

ल०/

द्विग्रन्थिपर निम्नः

प्रधान राज्यप

उत्तर प्रदेश अधिनियम मंच्या 26 सन् 1994
प्राधान तथा भू-संपत्ति की

उत्तर प्रदेश पराधान रथा भू-राजकृत दिवस । २६ सन् । १९९१

४३८ राष्ट्रविधि संशोधन । अधीनयम् । १९९५

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विविध अधीनियम, 1975 का अंगतर संशोधन करने के लिए

आधानयम्

भारत गणराज्य के पैतालिसें वर्ष में निम्नलिखित अधीनियम बनाया जाता है:-
१-४।४ यह अधीनियम उत्तर प्रदेश पराधान द्वारा भारतराज्य द्वारा

१२। यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरणार, अध्याचना नाम और प्रारम्भ

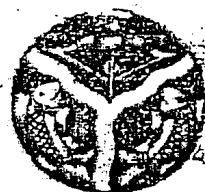
उत्तर प्रदेश
मीरी धीन्यम
संख्या ४ रान
पी धारा ३
संस्कारधन

२-हरत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, १९७५ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में खण्डखण्ड में, इब्द "पपास समय" के स्थान पर भाब्द "दो रात्रि-पपास समय" रख दिये जायें।

पाता 4 वा
संस्कृत

अन्नपूर्णायम की पारा 4 गे, उपधारा ४१४ में स्थान पर अन्नपूर्णायम

प्राचीन विषयों के साथ एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाली विद्या है। इसमें विभिन्न विषयों की जटिलताएँ और उनके सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। यह विद्या कई विद्यालयों में अपनी विशेषज्ञता वाली विद्या है।



राज. नं. रुप्र. ट्रॉट/पन. की. ४९५

साइरेस्ट नं. ३० डब्ल्यू ली०-४६

माहसून्य वा धोका एवं बाढ़ संस्थान

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

FAX

विधायी परिचय

भाग—1, छड़ (क)
(उच्च प्रदेश अधिनियम)

KIND ATTENTION:—U.P. TOURISM

1. JT. DIRECTOR, AGRA
2. DY. DIRECTOR, JHANSI
3. ASSTT. DIRECTOR, HARIWAR
4. Regional Tourist Officer,
VARANASI; GORAKHPORE;

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 जुलाई 1999
श्रावण 7, 1921 शक समवत्

ALLAHABAD, LUCKNOW
FAIZADABAD, MEERUT

Mr. P. S. D.
Asstt. Director
U.P. TOURISM
LUCKNOW

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1622/सभ्य-वि-1—1 (क) 31-1999

लखनऊ, 29 जुलाई, 1999

संघीन राज्यपाल नाहादाम

विधायक, 1999 मर. दिनांक 29 जुलाई, 1999 को अनुभवि

अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विविध

Kind Attention
DIRECTOR TOURISM (BULL.)
DEHRADUN

“आठ का संविधान” के अनुच्छेद 200 के मध्यीन राज्यपाल नाहादाम ने उत्तर प्रदेश विधान सभ्य द्वारा पारित प्रदान की ओर वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1999 के रूप में संविधान की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्त विधि (संशोधन), अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1999]

(जैसाकृउत्तरप्रदेश विधान सभ्य द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्त विधि अधिनियम, 1975 का अन्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गवर्नर के प्रत्यक्षे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बताया जाता है:—

— यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा मूराजस्त विधि (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1999 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश धर्मिः
निम्न संघर्षा ४
दन् १९७५ की
वार्ष ३ का प्रति
त्याक्षण

२—उत्तर प्रदेश कराचीत तथा भू-राजस्त विधि अधिनियम, १९७५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा द्वा दी जायेगी,
अधोरुपः—

“३—इस अव्याय में, जब तक सचिवों में अन्यथा अपेक्षित न हो :—
पाठभाष्य

(क) “अमरोकी पद्धति” का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबड़ का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि के भोजन का प्रभार सम्मिलित है और जिसमें शाय की चाम का प्रभार भी सम्मिलित हो सकता है;

(ख) “यरोपियन पद्धति” का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबड़ का नाश्ता का प्रभार भी सम्मिलित है;

(ग) “होटल” के मत्तर्गत ऐसी लाभादीय इकाई है जिसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हैं किन्तु इसके मत्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की मेंढ़ा गेस्ट योजना के अधीन अनुमोदित इच्छाइयां सम्मिलित नहीं हैं;

(घ) “सुख-साधन” का हात्पर्य ऐसी सुख-सुविधाओं से है जो किसी होटल में ऐसे कमरों या कमरों को कोष्ठावलि के जिनका किराया एक हजार रुपया प्रतिदिन जबका उससे अधिक हो, विभिन्न विभिन्न विभागों के लिए व्यवस्थित की जाय;

(इ) “सुख-साधन कर” या “कर”的 तात्पर्य धारा ५ के अद्योतक होठल कर से है;

(ब) “उपान्तरित अमरोकी पद्धति” का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबड़ का नाश्ता और दोपहर के भोजन वा रात्रि के भोजन में से किसी एक का प्रभार भी सम्मिलित है;

(छ) “स्वामी” का तात्पर्य होटल के स्वामी से है और उसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो होटल के प्रबन्ध का तत्काल योग्य प्रभारी हो;

(ज) “किराया” का तात्पर्य किसी होठल के कमरे या कमरों को कोष्ठावलि के अधिसौमो से वास्तविक रूप में प्राप्त किये गये तात्पर्य प्रभार; यह उसे इसी भी नाम से पुकारा जाय, से है और इसके मत्तर्गत वातानुकूलन, कलर, हीटर, चीजर, टेलीविजन, डेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त शैल्य या चित्रों से तिरित वस्तुओं भी उपलिखित हैं, किन्तु इसके मत्तर्गत भोजन या किये या ऐसी अन्य वस्तुओं के प्रभार, जिनको विक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर एकट, १९४८ के अधीन व्यापार कर देय है, सम्मिलित नहीं हैं।

स्पष्टीकरण-१ किसी कमरे या कमरों को कोष्ठावलि में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या का विचार किये बिना कमरे या कमरों की कोष्ठावलि को एक इकाई के रूप में मानकर कर का उद्घरण किया जायेगा। यहां कहीं स्वामी द्वारा विनियोग दीरिक योजनाओं, जैसे योग्यीय, कमरों का या उपान्तरित अमरोकी पद्धति के अधीन प्रभारों का एक सम्मिलित दर, जिसके मत्तर्गत आवास, भोजन और पैद तथा इसी प्रकार की अन्य भव्यों के प्रभार भी सम्मिलित हैं, जियत की जायी हो, वहां इस अधिनियम के अधीन कर का उद्घरण एक प्रभार के उस जाग पर जिस पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, १९४८ के अधीन व्यापार कर उद्घरणीय है, नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-२ वहां कहीं स्वामी द्वारा प्रभार की उद्घरण वसूली दैनिक दर से मिन्न दर के आधार पर की जाय, वहां कर का नियमित दर या कमरों की कोष्ठावलि के उपयोग को कुल अवधि के आधार पर संगणित और स्ट दैनिक प्रभार पर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-३ वहां कहीं स्वामी किसी प्रकार को छट प्रदान करता हो और प्रभारों की वसूली कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के लिये ईरिफ की मालिकता या अधिकार दर से मिन्न दर पर करता हो, वहां कर का उद्घरण स्वामी द्वारा प्रकाशित या घोषित प्रभारों पर न करके वास्तविक रूप से वसूल किये गये प्रभारों पर किया जायेगा।

दस्तावेज अधिनियम गजट, 29 जुलाई, 1999

3

—मूल अधिनियम की घाटा ५ में—

- (क) उपचार (1) में प्रतिबन्धात्मक चष्ट निकाल दिया जायेगा;
- (ख) उपचार (2) के द्वारा पर निम्नविभिन्न उपचार रह दी जायेगी;
अर्थात् :—

घाटा 4 का
दृष्टिकोण

“(2) सुख-भावन कर की संगणना करने में एक दर्पणे के ऐसे भाग को, जो पचास में से साँ उच्चारे विशिष्ट हैं, एक रूपया भास लिया जायेगा और जो पचास में से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा।”

—मूल अधिनियम की घाटा 4 के पश्चात् निम्नलिखित घाटा बढ़ा दी जायेगी;
अर्थात् :—

नई घाटा ५-ए
का बढ़ाया जाना

“५-क—(1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहत हुए जिन्हे वह अधिनियम की छूट और रोपित करे, किसी श्रेणी के हाटों, या किसी हाटों में विशिष्ट श्रेणी के आस्थगत सुख-भावनों को इस अधिनियम के अधीन देश-कर के पूर्ण मा किसी भाग के, भूगतान से, अधिसूचना द्वारा, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो, उस भूगतान कर सकती है या पांच वर्ष से अनादिक श्रद्धिके लिये ऐसे कर के पूर्ण मा किसी भाग के भूगतान के आस्थगत के लिये बनाऊ देसकती है।

(2) जहाँ किसी स्वामी ने उपचार (1) के अधीन किसी छूट या आस्थगत भूगतान कर लिया हो, और स्वामी द्वारा ऐसी छूट या आस्थगत की किसी शर्तों का बनापालन किसी भी कारण से नहीं किया गया है, वहाँ ऐसा उचामी छूट या आस्थगत की अद्वितीय के लिये कर का भूगतान करने के लिये दायी होगा मानो उसे ऐसी छूट या आस्थगत की जगता नहीं दी गयी थी।”

आमा है,
योगेन्द्र राम विपाठी,
प्रभुत्व सचिव।

No. 1622 (2)/XVII-V-1-1.(KA)-31-1999

Dated Lucknow, July 29, 1999

IN PURSUANCE OF THE PROVISIONS OF CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, THE GOVERNOR IS PLEASED TO ORDER THE PUBLICATION OF THE FOLLOWING ENGLISH TRANSLATION OF THE UTTAR PRADESH KARADHAN TATHA BHOO-RAJASHWA VIDHI (SAMSHODHAN) ADHINIYAM, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 1999) AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE AND ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON JULY 29, 1999.

THE UTTAR PRADESH TAXATION AND LAND REVENUE LAWS (AMENDMENT) ACT, 1999

[U. P. ACT NO. 34 OF 1999]

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws (Amendment) Act, 1999.

Short title

Substitution of
section 3 of U.P.
Act no. 8 of 1975

2. For section 3 of Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“3. In this chapter unless the context otherwise requires—

Definitions

(a) “American Plan” means the tariff plan in which the rent of the room includes the charges for the breakfast, the lunch and the dinner and may include the charges for the evening tea ;

(b) “Continental Plan” means the tariff plan in which the rent for the room includes the charge for the breakfast ;

(c) “hotel” includes an accommodational unit wherein rooms are provided to the customers on rent, but does not include the units approved under the ‘‘Paying Guest Scheme’’ of the Department of Tourism of the Government of Uttar Pradesh ;

(d) “Luxuries” means such amenities as are provided in a hotel to the occupants of such rooms or suites therein at carry a rent of rupees one thousand or more per day ;

(e) “luxury tax” or “the tax” means the tax levied under section 4 ;

(f) “Modified American Plan” means the tariff plan in which the rent of the room includes the charges for the breakfast, and one meal, either lunch or dinner ;

(g) “proprietor” means the owner of the hotel and includes the person, who, for the time being, is incharge of the management of the hotel ;

(h) “rent” means the aggregate of all charges by whatever name called, actually received from the occupant of a room or suite in a hotel and includes charges for air-conditioning, cooler, heater, geyser, television, radio, music, entertainment, extra bed, or linen articles but does not include the charges for food or drinks or such other items, on the sale of which trade tax is payable under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

Explanation—1—Irrespective of the number of persons staying in a room or suite the tax shall be levied, considering the room or the suite as a unit. Wherever a composite rate of charges has been fixed by the proprietor including charges of accommodation, food and drinks and the like under the various tariff plans such as, Continental, American or Modified American Plan, the tax under this Act shall not be levied on that part of such charges on which Trade Tax is leviable under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

Explanation—2—Wherever the charges are realized by the proprietor on the basis of a rate, other than the daily rate, the assessment of the tax, shall be made on the average daily charges calculated on the basis of the total period of use of the room or suite.

Explanation—3—Wherever the proprietor gives any kind of discount and realize charges at a different rate than the published or declared rate of tariff for the rooms or suites, the tax shall be levied on the charges actually realized and not on the charges published or declared by the proprietor.”

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) In sub-section (1) the proviso shall be omitted ;

(b) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(2) In computing the luxury tax a fraction of a rupee which is fifty paise or more shall be taken as rupee one and which is less than fifty paise shall be ignored.”

Amendment of
section 4.

4. After section 4 of the principal Act the following section shall be inserted, namely :—

Inspection -
new section 4-A

*4-A (1) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it is necessary so to do in deferment of tax the public interest, by notification, exempt any class of hotels or any specific class of luxuries provided in a hotel from payment of the whole or any part of the tax payable under this Act or allow for deferment of the payment of the whole or any part of such tax, for a period not exceeding five years.

(2) Where a proprietor has availed of any exemption or deferment under sub-section (1) and any of the conditions for such exemption or deferment has not been complied with by him for any reason whatsoever, then, such proprietor shall be liable to pay the tax for the period of exemption or deferment as if such exemption or deferment had not been allowed to him."

By order,
Y. R. TRIPATHI
Pramukh Sazhi

५८

३८५

४३

sh
Ro
e
b

ચોં દર્શા કું લો—એ કો ૧૧ રૂપ નિશા—(૮૨૪)—૧૯૯૯—૮૫૦ (૯૫૦)

